

लोकसभाध्यक्ष दुविधापूर्ण विडंबना में फंसे

उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को तो पुस्तक के अंश उद्धृत करने दिए पर राहुल गांधी को पूर्व सेनाध्यक्ष नरवाणे की पुस्तक के अंश पढ़ने की इजाज़त नहीं दी

- रेणु मिश्रल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 4 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब नहीं दे सके क्योंकि लोकसभा में विपक्ष ने भारी हंगामा किया। राहुल गांधी को लद्दाख में चीन के हमले पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब के बारे में बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद यह हंगामा हुआ।
ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री कल लोकसभा में भी भाषण नहीं देंगे और संभव है कि वह राज्यसभा में जवाब दें, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है।

हालांकि सूत्रों का कहना है कि सरकार आखिरी कोशिश कर रही है कि गतिरोध खत्म हो और विपक्ष से बातचीत शुरू हो सके। इसके लिए भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोले गए सभी आपत्तिजनक शब्द हटाए जा सकते हैं। वह किताबों से उद्धरण दे

- लोकसभाध्यक्ष की इस “विवादपूर्ण” व्यवस्था के कारण, कांग्रेस ने भारी हंगामा किया और प्र.मंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का उत्तर नहीं देने दिया।
- राहुल गांधी ने भाजपा सदस्यों की आपत्ति, कि पूर्व सेनाध्यक्ष नरवाणे की किताब अभी प्रकाशित हुई नहीं हुई उस अप्रकाशित पुस्तक के अंश कैसे लोकसभा में पढ़े जा सकते हैं, के जवाब में कहा, वे प्रकाशित पुस्तक की प्रति साथ लाए हैं, तथा उसकी प्रति प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे, जब प्र.मंत्री सदन में आएंगे।
- इस विवादित प्रकरण का अन्य पहलू यह भी है कि वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह व गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में दावा किया था कि पूर्व सेनाध्यक्ष की पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, पर, राहुल गांधी ने कहा कि वे पुस्तक की प्रतिलिपि सदन में लाए हैं।
- तो क्या कांग्रेस, वरिष्ठ मंत्रीगणों के खिलाफ मिथ्यावचन का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन का मामला बनाएगी।

रहे थे और स्पीकर ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की।
विपक्ष ने पूछा कि, क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडुला ने सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के साथ व्यवहार के अलग-अलग मानदंड अपना रखे हैं।
इसी के विरोध में कांग्रेस सांसद स्पीकर के कक्ष में पहुंच गए और उनसे

कड़ा विरोध जताया। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी को पत्रिका के लेख से उद्धरण देने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, जबकि निशिकांत दुबे को ऐसा करने दिया गया।
इस मुद्दे पर स्पीकर मुश्किल स्थिति में नजर आ रहे हैं।
एक दिलचस्प घटनाक्रम में राहुल

गांधी संसद में जनरल नरवणे की किताब को एक प्रति लेकर आए। उन्होंने मीडिया को वह किताब दिखाई और कहा कि जब प्रधानमंत्री सदन में आएंगे तो वह उन्हें इसकी एक प्रति देंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आएंगे।
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल और मंत्री बिट्टू के बीच झड़प

- जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 फरवरी। आज सुबह संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई। दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदर्शन के दौरान गांधी ने पूर्व कांग्रेस नेता को "गद्दार दोस्त" कहा। इसके जवाब में बिट्टू ने गांधी को "देश का दुश्मन" बताया।
बिट्टू तीन बार सांसद रह चुके हैं और रेलवे राज्य मंत्री हैं। उन्होंने 2024

- राहुल गांधी जब कांग्रेस सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर धरना दे रहे थे, तो वहां से गुजर रहे मंत्री रवनीत बिट्टू, जो पहले कांग्रेस में थे, को उन्होंने "गद्दार दोस्त" कहा, बदले में बिट्टू ने उन्हें "देश के दुश्मन" करार दिया।

लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा जॉइन कर ली थी।
यह छोटी बहस उस समय हुई जब संसद के मकर द्वार के पास कांग्रेस सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। जब बिट्टू पास से गुजरे तो गांधी ने कहा, " देखो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को अपना “राजनीतिक मंच” बनाया

न्यायालय ममता जी की इस रणनीति का “बेबस” मूकदर्शक बनकर रह गया और ममता जी को निर्बाध रूप से पन्द्रह मिनट तक मुख्य चुनाव आयुक्त को भला-बुरा कहने का पूरा मौका मिला

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 फरवरी। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख, ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य जजों के सामने चल रही कानूनी सुनवाई को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय के खिलाफ एक राजनीतिक भाषण में बदल दिया और इसमें बड़ी जीत हासिल की।
ममता बनर्जी ने बेहतरीन तरीके से राजनीतिक चाल चली और कोर्ट की कार्यवाही को बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई में बदल दिया। बनर्जी ने राज्य में अपने समर्थकों से वादा किया था कि वह बंगाल में मतदाता सूची का संशोधन बिल्कुल नहीं होने देंगी।
अब जब मतदाता सूची का संशोधन (रोल रिविजन) लगभग पूरा

- इस दुःखद घटनाक्रम का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि पश्चिम बंगाल में फर्जी मतदाता की रणनीति को तृणमूल कांग्रेस ने एक कला का रूप दे दिया है, निरंतर सुधार-संवार कर।
- 56 लाख से भी ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए थे, गत सूची पर गहराई से काम करने से। इसके अलावा गत सूची में बहुत से नाम उन व्यक्तियों के हैं, जो मृत हो चुके हैं तथा नियमित रूप से बांग्लादेश से, सीमा पार से, गैर कानूनी घुसपैठिए आकर चुनावों में मतदान करते रहे हैं।
- एसआईआर (वोटर सूची का शुद्धिकरण) 4 नवंबर 2025 को आरंभ हुआ था। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में परिवर्तन की अंतिम तारीख 19 जनवरी थी और फाइनल सूची 14 फरवरी को प्रकाशित होनी है।

हो चुका था और प्रक्रिया समाप्त होने वाली थी, तब ममता को लगा कि उन्हें बड़ा झटका लगा है। पिछली मतदाता

सूचियों से बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भूमिगत “चिकन नैक” रेल्वे ट्रैक बिछाने का काम शुरू

चिकन नैक एक संकड़ा भू भाग है, जो देश के नॉर्थ ईस्ट भाग को शेष भारत से जोड़ता है

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 4 फरवरी 'चिकन नैक' की सुरक्षा से जुड़े 'शीर्ष प्राथमिकता' वाले प्रोजेक्ट के तहत 40 किलोमीटर लंबे भूमिगत रेल कॉरिडोर के निर्माण का काम जल्द ही तेजी से शुरू किया जाएगा, यह दावा नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) के अधिकारियों ने किया है।
बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से घिरे तथा सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर-जिसे 'चिकन नैक' भी कहा जाता है-के माध्यम से ही पूर्वोत्तर राज्यों का शेष भारत से जमीनी होपक संभव है। भारत की सबसे कमजोर कड़ी कहे जाने वाले इस संकरे भू-भाग की चौड़ाई लगभग 20-22 किलोमीटर है और यह चीन की चुम्बी घाटी से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
हाल के महौनों में बांग्लादेश के

- 20-22 किलोमीटर चौड़ा, यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे ही चिकन नैक कहते हैं, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और चीन की सीमा से मात्र 130 किलोमीटर दूर है।
- बांग्लादेश के चीन के करीब जाने व चीन की मदद से चिकन नैक हथियाने के दावों के मद्देनज़र भारतीय रेल्वे ने भूमिगत रेल्वे ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया है, क्योंकि किसी भी संकट की स्थिति में भी अंडरग्राउण्ड ट्रैक बाधित नहीं होगा।

चीन के करीब जाने के बाद 'चिकन नैक' को लेकर कूटनीतिक तनाव बढ़ा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूहों ने भारत के पूर्वोत्तर भाग को अलग-थलग करने के उद्देश्य से चिकन नैक को जाम करने की खुली अपील की है, साथ ही कुछ उग्रवादी संगठनों ने इस कॉरिडोर को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की अपनी परिकल्पना का हिस्सा बताया है।
इस खंड में भूमिगत रेल लाइन

बनाकर भारत संभावित सुरक्षा खतरों से निपटना और सीमावर्ती क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है। एनएफआर के महाप्रबंधक चेतन श्रीवास्तव ने कहा कि यह रेल खंड पश्चिम बंगाल में टिन माइल हाट से रंगापाानी स्टेशन तक चलेगा।
2017 में चीन के साथ डोकलाम गतिरोध के दौरान सैन्य योजनाकारों ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बोत्सवाना से 8 चीते 28 को मध्यप्रदेश आर्येंगे

भोपाल, 04 फरवरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर असम से जंगली भैंसा मध्यप्रदेश लाने की प्रक्रिया सहित विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की।
■ असम से जंगली भैंसे भी मध्यप्रदेश लाने की तैयारी चल रही है।

उन्होंने बताया कि 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 चीते मध्यप्रदेश लाए जाएंगे। चीतों के पुनर्स्थापन को लेकर केंद्रीय मंत्री यादव से आवश्यक व्यवस्थाओं एवं सहयोग पर भी विस्तार से चर्चा हुई है।

डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास, रिजर्व फॉरेस्ट के विस्तार और वन्य जीव संरक्षण की असीम संभावनाएं हैं। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प.बंगाल चुनावों पर देर रात भाजपा की बैठक

मंगलवार देर रात केन्द्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के घर हुई इस मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन भी मौजूद थे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 फरवरी। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले मंगलवार देर रात पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर एक अहम बैठक दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री और भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार के आवास पर हुई।

बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल से भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा सांसद और पार्टी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह-प्रभारी बिप्लव देब भी चर्चा में शामिल हुए।
यह बैठक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए आगे की रणनीति तय करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। इसमें संगठनात्मक मजबूती, बुध-स्तरीय योजना और समग्र चुनावी रोडमैप पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक का प्रमुख फोकस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा

- बैठक का फोकस मुख्य रूप से एसआईआर के संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रणनीति का जवाब देने पर रहा, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी ने बेहद आक्रामक रुख अपना रखा है।
- मीटिंग में पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद शामिल हुए तथा पार्टी अध्यक्ष नबीन ने हरेक सांसद के साथ अलग-अलग मुलाकात कर फीडबैक लिया।
- सांसदों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में केन्द्रीय बजट को “यंग इंडिया” बजट के रूप में प्रचारित करें। इसके अलावा राज्य सरकार की विफलताओं पर आक्रामक रुख अपनाने और आंदोलन करने का निर्देश दिया गया, साथ ही कहा गया कि चुनाव होने तक आंदोलन जारी रहने चाहिए।

एसआईआर मुद्दे से निपटने की रणनीति पर था। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद हैं और उन्होंने मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया।

करीब तीन घंटे चली इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने की। सभी सांसदों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर बजट 2026 के प्रमुख प्रावधानों को जनता के बीच स्पष्ट रूप से रखें। युवाओं तक पहुंच बनाने पर विशेष ज़ोर दिया गया

और बजट 2026 को यंग इंडिया का बजट के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति बनाई गई है।
भाजपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए एक बड़ा और दीर्घकालिक प्लान तैयार किया है। इसी योजना के तहत नितिन नबीन ने सांसदों के साथ एक-एक कर व्यक्तिगत बैठकें कीं और उनसे सीधे फीडबैक लिया।
सांसदों को जमीनी स्तर पर राज्य सरकार की विफलताओं को आक्रामक तरीके से उजागर करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, स्थानीय मुद्दों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जोन-वार आंदोलन शुरू करने को कहा गया है। रणनीति यह है कि इन आंदोलनों को विधानसभा चुनाव तक लगातार सक्रिय रखा जाए।
भाजपा सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल चुनावों तक सांसदों से नियमित फीडबैक लिया जाता रहेगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी की कट-ऑफ पर नोटिस जारी किये

नयी दिल्ली, 4 फरवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट-पीजी 2025-26 की परीक्षा के लिए कट-ऑफ पर्सेन्टाइल कम करने के राष्ट्रीय चिकित्सा परीक्षा बोर्ड के निर्णय को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका

- राष्ट्रीय चिकित्सा परीक्षा बोर्ड ने 13 जनवरी को कट-ऑफ पर्सेन्टाइल असामान्य रूप से कम कर दिया था।

पर बुधवार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने इस चुनौती पर गौर किया और निर्देश दिया कि मामले को छह फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
याचिका में परीक्षा बोर्ड की 13 जनवरी की उस अधिसूचना पर सवाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 फरवरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले की पैरवी स्वयं की। उन्होंने राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (एसआईआर) के खिलाफ दायर अपनी याचिका के समर्थन में दलीलें दीं।
ममता बनर्जी एक प्रशिक्षित अधिवक्ता हैं और वे पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन गई हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले पर खुद बहस की। इसके लिए उन्होंने अदालत में एक अंतरिम आवेदन दायर कर अनुमति मांगी थी।
ममता लंबे समय से राज्य में

- ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर इसकी अनुमति मांगी थी। ज्ञातव्य है कि ममता बनर्जी ने कहा था कि वे खुद एक वकील हैं और एसआईआर पर अपना केस खुद लड़ींगी।
- ममता बनर्जी लम्बे समय से एसआईआर का विरोध कर रही हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव, 2025 की मतदाता सूची पर ही होने चाहिए।
- ममता बनर्जी ने एसआईआर में भारी विसंगतियों का आरोप लगाया और कहा कि कई महिलाओं के नाम इसलिए हटा दिए क्योंकि उन्होंने विवाह के बाद भारतीय परम्परा के तहत पति का सरनेम लगाना शुरू कर दिया था।
- सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि एसआईआर के संबंध में गणमान्य व्यक्तियों को नोटिस भेजते समय सावधानी बरते। ज्ञातव्य है कि चुनाव आयोग ने पूर्व नौसेना एडमिरल अरूण प्रकाश, नोबल विजेता अमर्त्य सेन व क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी नोटिस भेजे हैं।

एसआईआर अभियान का विरोध करती रही हैं और चाहती हैं कि आगामी मसौदा मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित होने की उम्मीद है, हालांकि सूची के आधार पर कराए जाएं।

उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि असम में, जो एक भाजपा-शासित राज्य है, एसआईआर प्रक्रिया क्यों नहीं कराई गई।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर 4 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी और मसौदा मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित हुई। दावे और आपत्तियां दर्ज

कराने की अंतिम तिथि 19 जनवरी थी। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी की प्रकाशित होने की उम्मीद है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रगति को

देखते हुए समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।
उनके वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अनमैड मतदाताओं का हवाला दिया और कहा कि सुधारात्मक कदम उठाने के लिए बहुत कम समय बचा है।
बार एण्ड बैच ने दीवान के हवाले से कहा, अनमैड मतदाता 32 लाख हैं। तार्किक विसंगति सूची में 1.36 करोड़ नाम हैं और 63 लाख मामलों की सुनवाई लंबित है।"
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दो याचिकाओं में नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शरद पवार ने सुनेत्रा से मुलाकात की

बारामती (महाराष्ट्र), 04 फरवरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को परिवार के मुखिया के रूप में नरम रुख दिखाया। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय के सवाल पर उन्होंने कहा कि

- इससे पहले उन्होंने अजित पवार के बेटों के साथ बंद कमरे में मीटिंग की थी।

कोई भी फैसला लेने से पहले अभी एक-दूसरे का साथ देना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कुछ दिन पहले उन्होंने रास्ता बंद (रोड ब्लॉक) वाला बयान दिया था।
शरद पवार ने दिवंगत अजित पवार के बेटों से बंद कमरे में मुलाकात की। इसके बाद वह बारामती में सुनेत्रा पवार के घर गए तथा अजित पवार को श्रद्धांजलि दी।
वरिष्ठ नेता शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर भी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में ‘‘गाली’’ निकाली

मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने इस पर आपत्ति जताई तो सभापति ने अपशब्दों को सदन की कार्यवाही से हटवाया

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर। पूर्व यूडीएच मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में ‘‘गाली’’ निकाल दी। जिस पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आपत्ति जताई, इसके बाद सभापति ने उनके द्वारा बोले गए अपशब्दों को सदन की कार्यवाही से बाहर निकलवाया।

दरअसल धारीवाल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कहा था कि ‘‘अगर लाखों युवाओं को स्मिफिट ट्रेनिंग देकर रोजगार योग्य नहीं बनाया तो यह युवा आबादी चुनौती बन जाएगी।’’ उनके इस बयान के बीच सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा ‘‘ इस देश में एक युवक को छोड़कर सबको रोजगार मिल गया।’’ इस दौरान गर्ग को जवाब देते हुए धारीवाल ने कहा, आपकी बात आधी समझ आती है...लेकिन आधी नहीं। इसी दौरान धारीवाल ने गर्ग को संबोधित करते हुए गाली निकाल दी।

धारीवाल की बात खत्म करने के बाद सरकारी मुख्य सचेतक ने खड़े होकर आपत्ति जतायी। उन्होंने कहा कि आदत के मुताबिक धारीवाल ने आज सदन में फिर्त गाली दी है, उसे सदन की कार्यवाही से हटया जाए। जिस पर सभापति ने गाली को कार्यवाही से हटाने के

- इससे पूर्व धारीवाल ने प्रधानमंत्री कौशल योजना में 10 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया।
- उन्होंने सड़कों के मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी द्वारा सदन में दिए गए जवाब में भी झूठ बोलने के आरोप लगाए

आदेश दिए। ज्ञात रहे कि शांति धारीवाल पहले भी सदन में गाली दे चुके हैं, उस वक़्त भारी हंगामा हुआ था और उन्हें सदन से माफ़ी मांगनी पड़ी थी।

इससे पहले शांति धारीवाल ने जहां प्रधानमंत्री कौशल योजना में 10 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। वहीं सड़कों के मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी पर भी सदन में झूठ बोलने के आरोप लगाए। धारीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल योजना को लेकर सीएजी ने संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें 10 हजार करोड़ के घोटाले की बात कही है।

रिपोर्ट में एक करोड़ 32 लाख में से 95 प्रतिशत लाभार्थी फर्जी पाए गए हैं। धारीवाल ने

आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से फर्जी स्किल सेंटर खुलवा दिए हैं, इसलिए घोटाला किया गया है। बैंक खातों का कोई विवरण नहीं है, फर्जी फोटो और फर्जी फिंगरप्रिंट और एक मोबाइल नंबर से लाखों लोगों को भुगतान किया गया है। धारीवाल ने कहा कि जिन युवाओं ने आपको सत्ता में बैठाया है, कल वही आपके लिए चुनौती बन सकते हैं।

हमारे कार्यकाल में 70 हजार किमी सड़कें बनीं

शांति धारीवाल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री दीया कुमारी ने सदन में कहा है कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में 13,160 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी की एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो 2024–25 में आई थी, उसमें पेव नंबर 12 पर लिखा है कि कांग्रेस के शासन में 70 हजार किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कें बनाई गई हैं। धारीवाल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सदन में झूठ बोला है।

धारीवाल ने कहा कि भाजपा के 2 साल के शासन में 14,800 किलोमीटर की सड़क बनाने की बात कही गई है, जबकि हमारी सरकार के दो साल के शासन में ही 23 हजार 585 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। यह भी

पीडब्ल्यूडी की एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इस तरह से झूठे भाषण सदन में नहीं देना चाहिए था।

नाम हटाने से विचारधारा खत्म नहीं होगी

धारीवाल ने कहा कि भाजपा की सरकार ने एक-एक करके हमारी सारी योजनाओं के नाम बदल दिए हैं और अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। हमने जो योजनाएं शुरू की थीं, उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि वो गरीबों, छात्रों और मजदूर किसानों के हित की योजनाएं थी। मनरेगा में ग्राम सभा का अधिकार केंद्र सरकार ने छीन लिया है।

शांति धारीवाल ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को दुनिया से हटाया, लेकिन केंद्र सरकार ने अहिंसा के आविष्कार करने वाले महात्मा गांधी का नाम ही योजनाओं से हटाना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि ‘‘महात्मा गांधी का नाम दुनिया की जबान, दुनिया के दिल और दुनिया के दिमाग से नहीं निकाल पाओगे। महात्मा गांधी की मूर्तियां 80 देशों में लगी हुई हैं, लाखों की तादाद में लोग उनके दर्शन करने आते हैं।’’

‘‘खेजड़ी बचाओ’’ आंदोलन का मुद्दा विधानसभा में गूंजा

कांग्रेस विधायक डुंगरराम ने कहा कि ‘‘लाखों लोग महापड़ाव में बैठे हैं, 29 संत और 339 पुरुष आमरण अनशन पर हैं, इसके बावजूद राज्य सरकार ने किसी से वार्ता नहीं की।’’

जयपुर (विसं)। विधानसभा में शुन्यकाल में पच्ची के जरिए मामला उठाते हुए कांग्रेस विधायक डूंगर राम गेदर ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण बचाओ, खेजड़ी बचाओ समिति बिस्नोई समाज की अगुवाई में पिछले दो साल से बीकानेर में आंदोलनरत है, लेकिन खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई उसके बावजूद भी हो रही है। खेजड़ी राज्य वृक्ष है, इसे बचाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। गेदर ने कहा कि सरकार को पता था इसके बावजूद आंदोलनकारियों से कोई बातचीत नहीं की।

लाखों लोग महापड़ाव में आए। आज तीसरे दिन भी 29 संत अन्न, जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठे हैं। करीब 339 पुरुष अन्न,जल त्याग कर बीकानेर में आमरण अनशन पर बैठे हैं। तीन धरतार्थियों की तबीयत खराब हो चुकी है, कोई सरकार का प्रतिनिधि वहां

- नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा कि ‘‘साधु संत धरने पर बैठे हैं। सरकार की इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि उनसे बातचीत करें’’

पर नहीं गया। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि साधु संत धरने पर बैठे हैं। सरकार की इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि उनसे बातचीत करें। खेजड़ी राज्य वृक्ष नहीं देव वृक्ष भी है, लोग पूजते हैं। आप लोगों ने आंखें बंद कर रखीं हैं। कांग्रेस विधायक डुंगरराम गेदर ने कहा कि 10 नवंबर 2024 को जब बिस्नोई समाज ने राष्ट्रीय स्तर पर खेजड़ी बचाने के लिए महापड़ाव



जयपुर। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सेवानिवृत्त उपनिदेशक डॉ. लीलाधर दोचानिया के नव प्रकाशित कविता संग्रह ‘‘जिन्दगी मुस्कराते रहे’’ का विमोचन शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। विमोचन वरिष्ठ साहित्यकार और लेखक त्रिलोक चंद कौशिक करेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित साहित्य संगीत और चित्रकला के त्रिआयामी उत्सव पिकनैफेस्ट के दौरान महाराष्ट्र के वरिष्ठ साहित्यकार मनीषा खटाते सहित विभिन्न स्थानों के अनेक लेखक भाग लेंगे। संयोजन सीमा वालिया करेंगी।

भजनलाल सरकार ने मजबूत की प्रदेश में महिला सुरक्षा : बेढ़म

जयपुर। राजस्थान 16वें विधानसभा के पंचम सत्र के दौरान बुधवार को विधानसभा परिसर में मॉडिया से रूबरू होते हुए गुह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने प्रदेश में महिला अपराधों की स्थिति, कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर विस्तृत जानकारी दी।

मंत्री बेढ़म ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है और अपराधों में कमी देखने को मिली है। गुह राज्य मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2019 में महिला अत्याचार के 41 हजार 155 प्रकरण दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2023

में यह संख्या 42 हजार 174 रही। इसके बाद वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रभावी पुलिस कार्रवाई और संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था के कारण वर्ष 2024 में प्रकरण घटकर 37 हजार 700 रह गए तथा वर्ष 2025 में 37 हजार 981 प्रकरण दर्ज हुए।

उन्होंने कहा कि यह कमी पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, त्वरित अनुसंधान और सरकार की प्राथमिकताओं का परिणाम है।

उन्होंने बताया कि अनुसंधान अधिकारियों को 60 दिवस की निर्धारित अवधि में जांच पूरी कर न्यायालय में पेश करने के निर्देश हैं।

थाईलैंड की राजकुमारी 6 से 10 फरवरी तक रहेंगी राजस्थान प्रवास पर

मुख्य सचिव ने की रॉयल थाई एम्बेसी की एम्बेसडर चवनार्ट थांगसुमफैंट के साथ तैयारियों की समीक्षा

जयपुर (कासं)। थाईलैंड की राजकुमारी प्रिंसेस सिरिविक्नावरी नारितताना राजकन्या 6 से 10 फरवरी तक राजस्थान प्रवास पर रहेंगी। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने उनकी यात्रा प्रवास को लेकर बुधवार को शासन सचिवालय में रॉयल थाई एम्बेसी की एम्बेसडर चवनार्ट थांगसुमफैंट सहित थाई एम्बेसी और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान की पूरे विश्व में अतिथि देवो भवः की परंपरा की अपनी अनूठी पहचान है। ऐसे में प्रिंसेस सिरिविक्नावरी नारितताना राजकन्या की मेहमान नवाजी का अवसर मिलना राज्य के लिए हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि थाई राजकुमारी का यह दौरा भारत-थाईलैंड संबंधों में और अधिक गहरे सामरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहित करेगा।

मुख्य सचिव ने प्रिंसेस की यात्रा के दौरान पुलिस तैयारियों, सुरक्षा इंतजामों, यातायात व्यवस्था, प्रोटोकॉल, संबंधी समस्त पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। प्रिंसेस सिरिविक्नावरी नारितताना राजकन्या अपने प्रवास के दौरान जयपुर एवं जोधपुर का भ्रमण करेंगी। जयपुर में वे आमेर किला, हवामहल, सिटी पैलेस, त्रिपोलिया बाजार सहित अन्य प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का अवलोकन करेंगी। इसके पश्चात जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, उममेद चवन पैलेस, जसवंत थड़ा सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण प्रस्तावित है। इस दौरान उन्हें राजस्थान की समृद्ध हस्तशिल्प कला, शिल्पकला, संस्कृति,



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने थाईलैंड की राजकुमार के राजस्थान यात्रा प्रवास को लेकर बुधवार को सचिवालय में बैठक ली। उन्होंने रॉयल थाई एम्बेसी की एम्बेसडर चवनार्ट थांगसुमफैंट सहित थाई एम्बेसी और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ तैयारियों पर चर्चा की।

विरासत एवं पारंपरिक आतिथ्य से भी अवगत कराया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन,

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग नवीन जैन, महानिदेशक पुलिस, (कानून एवं व्यवस्था) संजय कुमार अग्रवाल, जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम, आयुक्त पर्यटन विभाग रुक्मणि जुड़े।

‘ धौराला में रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन कार्य अग्रिम चरण में है ’

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि अनेकर जिले की राजगढ़ तहसील के धौराला राजस्व गांव में रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन का काम अग्रिम चरण में है।

कर्नल राठौड़ प्रश्नकाल में विधायक मांगेलाल मीना के पूरक प्रश्नों के पात्र परिवारों के साथ पृछा था। राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ उपयुक्त जमीनों को चिह्नित कर लैंड बैंक भी तैयार कर रही है, ताकि उद्योगों की मांग के अनुरूप उन्हें समय पर भूमि उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि लक्ष्मणगढ़ में उपलब्ध भूमि प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एनसीजेड) में आने के कारण इसका उपयोग उद्योगों

ग्राम उत्थान शिविरों में अब तक 77 लाख प्रकरण निस्तारित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास धरातल पर हो रहे साकार



जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में ग्रामीणों तक सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित ग्राम उत्थान शिविरों में अब तक आमजन की 77 लाख से अधिक समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। अब 5 से 9 फरवरी तक ग्राम उत्थान शिविर का द्वितीय चरण शुरू किया जाएगा।

गत 23 जनवरी (बंसत पंचमी) से प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर इन शिविरों क

शुरुआत की गई थी और इनसे किसान, पशुपालक, महिला एवं

श्रमिक सहित विभिन्न वर्गों को एक ही छत के नीचे योजनाओं से

लाभान्वित किया जा रहा है। इससे प्रशासन और आमजन के बीच क

दूरी कम हुई है और आत्मनिर्भर एवं सशक्त ग्रामीण राजस्थान को गति

मिली है।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

रही है, जिससे ग्रामीणों की बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर

नहीं लगाने पड़े।

शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए

शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत परियोजनाओं को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे

भी करेगी।
प्रदेश में निवेशकों को
सेमीकंडक्टर यूनिट्स की स्थापना के
लिए राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से
आवेदन करना होगा। राजस्थान
सेमीकंडक्टर पॉलिसी की क्रियान्विति

पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अजित पवार ने एनसीपी (एसपी) के साथ विलय की कोई पहल नहीं की थी। शरद पवार ने कहा कि फडणवीस एनसीपी के दोनों गुटों के बीच हुई विलय संबंधी चर्चाओं का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्हें इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।

की सफल बसाहट के बाद अब असम का जंगली भैंसा भी मध्यप्रदेश के जंगलों में स्वच्छंद विचरण करता नजर आएगा।

उठाए गए हैं, जिसके माध्यम से स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश के लिए कट-ऑफ परसेंटाइल को उस स्तर तक कम कर दिया गया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने असामान्य रूप से बहुत कम बताया है। इसमें कट-अफ

ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ महिलाओं के नाम के कुवल इसलिफ हटा दिए गए क्यौंकि उन्होंने शादी के बाद अपना सरनेम बदल लिया। उन्होंने कहा, "मान लीजिए बेटी शादी के बाद ससुराल चली जाती है, वह पति का सरनेम इस्तेमाल कर रही है, इसे भी मिसमैच माना गया, कुछ बेटीयाँ ससुराल चली गईं, उनके नाम भी हटा दिए गए।"

बनर्जी ने नाम और उपनाम लिखने के अलग-अलग तरीकों की ओर ध्यान दिलाया, जो वर्तमान व्यवस्था का हिस्सा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे किसी भी अंतर के कारण मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं।

- कुकी समुदाय के भाजपा विधायक नेमचा किपगेन को उपमुख्यमंत्री बनाया गया

क रूप में शपथ ली है। भाजपा के गोविंदनाथ चौधौज और एनपीपी केकेलेमन सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। नेमका किपगेन ने नई दिल्ली स्थित मणिपुर भवन से डिजिटल माध्यम से शपथ ली। विधायक दल की मंगलवाकर को बैठक हुई, जिसमें खेमचंद (62 वर्षीय) को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। राष्ट्रीय राजधानी पार्टी मुख्यालय में भाजपा विधायक दल

की डेड घंटे बैठक चली, जिसमें केन्द्रीय कमेटी के सदस्यों ने भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी, पर्यवेक्षक तरुण चूधरी की उपस्थिति में भाजपा मुख्यालय में विस्तार से हुई विचारक दल की बैठक में कई नामों पर विचार हुआ था। चर्चा थी कि कुली बनाम मैरिड समुदाय के बीच संतुलन साधने के लिए नई सरकार में कुली समुदाय को उपमुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। हालांकि, मुख्यमंत्री के मामले में लिए गए निर्णय से साफ था कि पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की पसंद को तज्जुबो नहीं मिलेगी। बीरेन दास बार के विधायक मैरिड समुदाय की ही गोविंद दास को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे।

मार्दान मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोशरो शर्मा द्वारा वनत प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हट्या, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा। आ.ए.आ.आ. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा ए.आ.आ.हाट, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय: पतायथा हाऊस, कन्नपति सिवाजी नगर, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आड्य मैने रोड आड्य, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:- वरूदा कालान, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665, जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डाना कार्यालय :- जी 1-201, रीठो औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डाना। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600-रूद्रत कालान, फेस-150, रीठो औद्योगिक क्षेत्र, चूरु, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908